Financial assistance to deep sea fishing industry

2107. SHRI SUBAS MOHANTY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what steps are being taken to assist the deep sea fishing industry by nationalised banks;

(b) whether it is a fact that the Banking department is directly supervising loans for fishing trawlers since Ist June, 1987;

(c) whether Government will consider directing the new organisation under the Ministry to give liberal financial assistance to owners of deep sea fishing trawlers; and

(d) whether small entrepreneurs can seek financial assistance from this organisation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) RBI has issued general guidelines to all scheduled banks for advances to priority sector, including fisheries. Advances to fisheries cover activities from fish catching to export of fish, as well as financing of equipment required for deep sea fishing. Financial assistance under priority sector is available from commercial banks by way of investment credit.

(b) The Shipping Development Fund Committee which used to provide loans for deep sea fishing trawlers was wound up with effect from 3rd April, 1987 and in accordance with the provisions of the Shipping Development Fund Committee (Abolition) Act, 1986, the obligations of the esrstwhile SDFC have been vested in the Central Govenment.

(c) and (d) The Shipping Credit and Investment Company of India has been set up in December 1986 for providing financial assistance, *inter-alia*, for the acquistion of merchant shipping vessels and certain deep sea fishing trawlers. Proposals for sanction of loans for above acquisitions are considered by SCICI, on the merits of each case, based on the economic and technical viability of the project.

2108. [*Transferred to the 18th August*, 1987].

भूमिहीन श्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा

2109. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 जून, 1987 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार जीवन बीमा निगम, गुजरात में आठ लाख भूमिहीन श्रमिकों के सामूहिक बीमे से संबंधित कार्यवाही आरम्भ कर दी है ;

(ख) क्या यह कार्य बिहार तथा अन्य राज्यों में भी आरम्भ किया जाएगा ; और

(ग) क्या यह योजना अन्य राज्यों में भी लागू है और यदि हां, तो जहां यह लागू है, उन राज्यों के नाम क्या हैं और वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (ग) जी, हां। गुजरात सरकार ने पहली अप्रैल, 1987 से आठ लाख भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए जीवन बीमा निगम से ग्रुप बीमा पालिसी ली है। यदि राज्य सरकारें ऐसी योजनाओं में भागीदार बनने की इच्छुक हों तो जीवन बीमा निगम को अन्य राज्यों (बिहार सहित) द्वारा इस प्रकार की ग्रुप बीमा योजनाएं प्रारम्भ करने में कोई आपत्ति नहीं है। अखिल भारतीय स्तर पर, जीवन बीमा निगम के परामर्श से भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए एक बीमा योजना शीघ्र शुरू की जा रही है, जिसकी प्रीमियम लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

पाकिस्तान द्वारा हथियारों की प्राप्ति पर भारत की प्रतिक्रिया

2110. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम, प्रक्षेपास्त्र आदि हथियार प्राप्त किये जाने